सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत से कारखाने तथा प्रबन्धक अच्छे है और मैं समझता हूँ कि वह निजी क्षेत्र पर काबू पा जायगा । वहाँ भ्रष्टाचार भी है परन्तु क्या निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है । वहाँ तेजा है तथा सुन्धरा है और कपड़े के मिल है । इसलिए यह कहना उचित नहीं कि भ्रष्टाचार केवल सरकारी क्षेत्र में ही है । यह निजी क्षेत्र में भी है । सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धक गुणों तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर नियुक्त करना चाहिए । वहां के प्रबन्धकों को उनके वेतनों के अतिरिक्त उत्पादन की किस्म पर कमीशन मिलना चाहिए । यदि आप ऐसा कर दें तो प्रबन्धकों के रवैये में परिवर्तन आ जायेगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार आ जावेगा । इससे चोरी समाप्त होगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी ।

उत्पादन शुल्क का अधिक लागू करना गलत है तथा इससे निर्वाह व्यय देशनाँक अधिक हो जावेगा । एकाधिपत्यों की आलोचना न करने की पद्धति गलत है । यदि आप बैंकों को निजी लोगों के हाथ में रहने देंगे तो आप देश की समस्या नहीं सुलझा सकेंगे ।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

सरकार विदेशी मुद्रा के चोरों के प्रति नम्र क्यों है ? बर्ड हेल्जर्स ने विदेशी मुद्रा की चोरी की तथा उन पर 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया । राजस्व बोर्ड ने इसे घटाकर 48 लाख रुपया कर दिया और इस प्रकार उन्हें 1 करोड़ रुपया ले जाने की अनुमति दे दी । यह नम्रता मेरी समझ से बाहर है । बर्ड हेल्जर्स का सम्बन्ध बिरला औद्योगिक साम्राज्य से है तथा वे अब यूरोपीय नहीं रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री महोदय का वक्तव्य होगा । आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं ।

पश्चिम एशिया की स्थिति के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEVELOPMENT IN WEST ASIA

प्रधानमंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) लगभग दो सप्ताह हुए मेरे सहयोगी वैदेशिक-कार्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया और पश्चिमी एशिया की भयंकर स्थिति के बारे में सरकार का मत व्यक्त किया ।

उसके बाद से सुरक्षा परिषद् तथा उससे बाहर हमारा प्रयत्न वहां तनाव को कम करने तथा शान्ति बनाये रखने में रहा है । हमारे प्रतिनिधि के प्रयत्नों की अच्छी प्रतिक्रिया हुई और यह आशा हुई कि सुरक्षा परिषद् की अगली बैठक में इस मामले में काफी प्रगति हो जावेगी ।

अभी उक्त प्रयत्न जारी थे कि कल इसराइल तथा संयुक्त अरब गण राज्य और अन्य अरब देशों के बीच संघर्ष के समाचार प्राप्त हुए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सुरक्षा परिषद् की आपात कालीन बैठक में सारा ब्यौरा दिया और यह भी बताया कि इसराइली वायुयानों ने संयुक्त अरब गणराज्य तथा सीरिया के क्षेत्रों पर आक्रमण किया।

मैं कठोर शब्द नहीं प्रयोग करना चाहती परन्तु जो सूचना मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि इसराइल ने इस सशस्त्र झगड़े को पूरी लड़ाई में परिवर्तन कर दिया है।

संसार को पश्चिमी एशिया में एक भयानक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है जहां इसराइल तथा अरब सेना एक दूसरे के विरुद्ध हैं और यदि यह लड़ाई रोकी नहीं गई तो एक बड़ी लड़ाई बन जायेगी। हमारे अपने राष्ट्रीय हित भी पश्चिमी एशिया की मजबूती से सम्बन्धित है। हमारा सबका कर्तव्य है कि इस खतरनाक स्थिति में पुनः शान्ति स्थापित की जाये।

सुरक्षा परिषद् में हमारा यह पूरा प्रयत्न हो रहा है कि सब सशस्त्र सेना 4 जून के स्थानों पर आ जावें।

सदस्यों ने इसराइली तोपखाने द्वारा अकारण गाजा स्थित संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के भारतीय सैनिकों की मृत्यु के समाचार पढ़े होंगे। यह आक्रमण जान बूझकर किया गया तथा बिना उत्तेजना के किया क्योंकि हमारे दल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निशान थे।

इस सम्बन्ध में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एक पत्र भेजा है जिसमें इन घटनाओं पर अपना दुःख तथा रोष प्रकट किया है और कहा है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा तथा लड़ाई क्षेत्र से शीघ्र निकालने के बारे में कारगर कदम उठाये जायें।

सरकार इन पांच सिपाहियों के परिवारों को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देगी जिन्होंने वहां अपना जीवन बलिदान किया। यह रकम उससे कम नहीं होगी जो उनके परिवारों को उस समय मिलती यदि यह युद्ध में मारे जाते। इसी बीच मैं प्रत्येक परिवार को 5000 रु० तात्कालीक सहायता के रूप में प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता निधि से भेज रही हूं।

मुझे विश्वास है कि यह सदन इस शान्ति के सिपाहियों पर जो आक्रमण किये गये उसकी भर्त्सना करेगा। महासचिव ने इसराइल सरकार से कड़ा विरोध किया है। सारे सदन की ओर से मैं इन दुःखी परिवारों को सदन की ओर से सहानुभूति के संदेश भेजना चाहती हूं कि उन बहादुरों ने मानवता तथा शान्ति के लिए अपना जीवन बलिदान दिया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें दो मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजली देने के लिए खड़े हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन चाहता है तो हम खड़े हो जायेंगे।

(इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे)
(The members then stood in Silenne for a short while)

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह कि बहुत से सदस्यों की बजाय प्रत्येक दल से एक एक सदस्य ही बोलें।

श्री रंगा (श्री काडला) : हमें इन पाँच जवानों की मृत्यु का दुःख है। वह वहां अपनी इच्छा से नहीं थे बल्कि वे शान्ति स्थापना का कार्य कर रहे थे। वहां एशिया के लिए एक और दुःख की घटना हो रही है। ऐसे मामले में हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कार्य करेगी जिससे सारे राष्ट्र की भावना प्रतिबिम्बित हों। परन्तु दुःख से कहना पड़ता है कि वह संतोषजनक नीति नहीं अपना रहे। इसके बारे में सरकार को इस सदन में हमने चेतावनी भी दे दी थी। कल हमने प्रधान मंत्री को एक पत्र भी लिखा है और सुझाव दिया है कि कम से कम अब तो वह सरकार को परामर्श दे कि एक रचनात्मक रवैया अपनाये।

श्री मु० यू० सलीम (नलगोंडा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने नियम संख्या 197 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया है तथा उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है। कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है और इस सदन में इस प्रकार के स्पष्टीकरण की प्रथा है। इसलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रंगा : महोदय प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है वहां शीघ्र युद्धविराम होना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधि से कहा है कि वह इसका प्रयत्न करे। फिर क्या कारण है कि इसके लिए किसी को दोषी ठहरा रहे हैं ? आज प्रातः बताया गया कि उनके पास सूचना है परन्तु जब हमने उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि वह समाचार पत्रों में आ गई है। अब हम भी दूसरों के साथ मिल गये हैं। हमें शान्ति के लिए प्रबल करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए अनाज भी उसी रास्ते से आ रहा है और लड़ाई के कारण उसमें देर हो गई है। इसलिए सरकार यदि वास्तव में तटस्थ रहना चाहती है तो फिर किसी की हिमायती नहीं करनी चाहिए।

Shri A.B.Vajpayee (Balrampur): Sir, the Prime Minister has lost the opportunity of having a national policy on the question of West Asia. I want to make it clear that we want to be friends with Arab countries.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय जब भी प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देती हैं तो विरोधी पक्ष के नेताओं को न केवल स्पष्टीकरण के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है बल्कि अपने विचार प्रकट करने का भी। मैं उस ओर के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह बे सबरी न दिखाये और व्यवधान न करे। यह एक खतरनाक कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : गत पांच छः दिन से उसके बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के नोटिस मेरे पास आ रहे हैं तथा सारे देश की इसमें रुचि है। इसलिए यदि कुछ सदस्य इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो बेसबरी नहीं दिखानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। दलों के नेताओं को भी अपनी बात कहने में अधिक समय नही लेना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): My party wants friendship with the Arab nations but not on the condition of annihilation of the Israel State. If they insist on the destruction of Israel we cannot accept their friendship.

The hon. Prime Minister should have made it clear in the House that India will not be a party in any efforts made to erase Israel from the map of the world and anybody who will attemp it will lose our sympathy. There are some countries among the Arabs, who are the instigator of the imperialist powers openly support Pakistan during the Indo-Pak conflict. I would, therefore say that we should formulate our foreign policy keeping in view all this and also the help and support given to us by the United Arab Republic at the time of Indo-Pak conflict. The help and support was not so as was expected.

Whereas in the United Nations we have adopted a moderate approach here in New Delhi we have acted in a hurry in branding the Israel as an agressor. I would request the hon. Prime Minister to place the relative data, information and its source on the Table of the House.

I would also like to know who is responsible for the death of our Jawans posted in the Gaza strip. Why they were not evacuated earlier? Wnether the arrangements are being made for eviction of the armymen who are still there.

श्री अंबाग्रासन (तिरूवेगोड) : हम भी उन भारतीय सिपाहियों के प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने शान्ति के लिए विदेशी भूमि में अपने जीवन का बलिदान दिया है।

ऐसे गम्भीर संकट में प्रधान मंत्री को यथासम्भव सभा की सहमति प्राप्त करनी चाहिये ताकि इस बारे में हमारी नीति में कोई दो मत न हों। हमें सामान्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस बारे में भी हमें गुटों से अलग रहने की नीति पर चलना चाहिए था। इसी नीति पर हम एक लम्बी अवधि से चल रहे हैं और यह शान्ति बनाये रखने में सहायक सिद्ध हुई है।

इस समय जब कि पश्चिमी एशिया में युद्ध भड़क उठा है और इसके अन्य भागों तक फैलने का भय है हमें अपने राष्ट्र की ओर से सावधानी से काम लेकर कोई वक्तव्य देना चाहिए था। विदेश नीति में सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अत्यावश्यक है। अतः प्रधान मंत्री को कोई व्यक्तव्य देने से पूर्व किसी अधिक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पांच सिपाही जिनको श्रृद्धांजलि देने के हेतु हम खड़े हुए इजराइल के आक्रमण से ही मारे गये हैं।

अरब लोगों के स्वतन्त्रता अन्दोलन में गड़बड़ करने के लिए ब्रिटिश तथा अमरीकन साम्राज्यवादियों के इशारे पर इजरायल बनाया गया है। पश्चिमी जर्मनी इजरायल को हथियारों से लैस कर रहा है जब कि हिटलर के हाथों यहूदियों को बहुत दुख उठाना पड़ा था।

यदि भारत साम्राज्यवाद में सम्मिलित न होकर गुटों से अलग रहने की नीति पर दृढ़ रहना चाहता है तो उसको साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों का समर्थन करना चाहिए

अर्थात् वर्तमान मामले में इजरायल नेतृत्व के विरुद्ध अरब लोगों का साथ देना चाहिए। सरकार को युद्ध-विराम कराने तथा युद्ध को फैलाने से रोकने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार अरबों के समर्थन की नीति पर अग्रसर रहे और इसी कारण हम सरकार की नीति का समर्थन करते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The Government is pursuing two different policies one in the U.N.O. and other in Delhi as regards the crisis of the West Asia is concerned. I have every appreciation for the work done in the Security Council by the Indian representative. The Government should adopt a positive policy of self respect whereby the countries partitioned by the imperialists could be united. Here I would say that Russians have the as much hand in the creation of the Israel as the Britishers and the American hand. Not only Israel but Jordon, Iraq and Saudi Arabia are all the creations of the imperialists.

The Pope has appealed that the jereusalam may be declared an open city. I would say that it would be better if the Government of India expresses its wrllingness in their favour.

We should not brand any body aggressor. Efforts should be made to bring cease-fire in this region.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : साम्राज्यवादी शक्तियां अपने तेल के हितों के कारण ही इजरायल और अरबों को लड़ाती रहती हैं। यही कारण है कि वह इनमें सुलह नहीं होने देते। आजकल अरब में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लहर उठ रही है। इस लहर को जागरूक करने में राष्ट्रपति नासिर सब से आगे हैं। साम्राज्यवादियों को भय है कि यदि अब नहीं तो भविष्य में किसी समय उनके तेल सम्बन्धी खतरे में पड़ सकते हैं।

जिसमें संयुक्त अरब गणराज्य के उपराष्ट्रपति तथा मंत्री अमरीका में बातचीत करने के लिए जा रहे थे उसी समय आक्रमण शुरू हो गया। युद्ध के आरम्भ होने से कुछ दिन पूर्व ही अमरीका तथा ब्रिटेन ने अकाबा खाड़ी को खोलने पर जोर दिया था। उसी समय इस छोटे से देश ने संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। इससे स्पष्ट है कि उसके पीछे किसी का हाथ था। इसलिए हमें अरबों की सहायता करनी चाहिए। मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने यही नीति अपनाई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपने दल के विचार व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे देश जिसने सदा देश के अन्दर तथा बाहर शान्ति के लिए कार्य किया है के नागरिक के नाते कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम सब की संसार के इस क्षेत्र में दिलचस्पी है क्योंकि यदि यह संघर्ष लम्बी अवधि के लिए जारी रहता है तो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें सर्व प्रथम अपने देश के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमें किसी दल का पक्ष न लेकर यथासम्भव शान्ति स्थापित कराने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : यह सच है कि सर्वप्रथम हमें शान्ति स्थापित करने के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए परन्तु उसी समय हमें यह भी देखना है कि किस दल का

दावा कितना उचित है। इस संसार में हम पड़ोसियों की तरह रहते हैं इसलिए जो कुछ हो रहा है उस बारे में हमें अपनी आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए।

पाकिस्तान-विरोधी धारणा के कारण ही कुछ लोग इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं। यदि हम इस बात की अनुमति देते हैं तो मुझे डर है कि चीन के विरुद्ध हमें फारमोसा को भी समर्थन देना पड़ेगा। इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): At this Juncture, the Prime Minister should have used restraint in her speech. She was expected to work for peace in the present circumstances but, unfortunately, her speech has been quite differently. Only time will tell the price India will have to pay for the same,

India does not have diplomatic relations with Israel. In these circumstances, how can Government of India blame her for having accelerated the war. I would like to know whether those, who thereatened to wipe out Israel from the map within four days, are not responsible for accelerating the war. The Government of India wants Israel to go back to June 4 position but what about the blockade of gulf of Agba, which is the real cause of war. The Prime Minister should explain her stand on this matter.

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : समूचा सदन किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति के पक्ष में है परन्तु उसका अर्थ यह है कि हम किसी विषय के गुणावगुणों के आधार पर उस बारे में निर्णय करने में स्वतन्त्र हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसके लिए एक पक्ष जिम्मेदार है, मेरे विचार में हमारी सरकार ने ठीक ही किया है।

हमें अपने उन वीरों की मृत्यु पर खेद है जो शान्ति स्थापित करने के लिए वहां गये और जिनकी मृत्यु होगई। इस मामले में केवल विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है। इस मामले को हमें स्वतन्त्र तथा साहसी देशों की भांति उठाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रधान मन्त्री के उत्तर देने से पहले मैं सभा को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, प्रधान मन्त्री को भी सभी बातों की जानकारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी एक घण्टा पहले समाचार मिला है कि.....

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा (अन्तर्वाधायें)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : **

श्री जी० मा० कृपलानी (गुना) : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि हम इस समय किसी को दोष दे सकें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सभी सदस्यों ने राष्ट्रसंघ में हमारे द्वारा अपनाये गये पक्ष का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो इससे उस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना में बहुत सहायता मिलेगी।

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमें इस विषय में अधिक सावधान रवैया अपनाना चाहिए। भारत की स्वतन्त्रता को लगभग 20 वर्ष हो चुके है। हमने सावधान रहकर विश्व पर कोई प्रभाव नहीं डाला है । न्याय तथा शान्ति के सम्बन्ध में दृढ़ रवैया अपना कर हमने विश्व पर अपना प्रभाव डाला है । गुटों से अलग रहने की नीति का अभिप्राय यह नहीं है कि हमें तटस्थ रहना चाहिये । कोई विचारशील व्यक्ति घटनाओं को देखकर निस्प्रभावित नहीं रह सकता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा है कि क्या अकाबा की खाड़ी में संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यवाही ही युद्ध का कारण है । मैं नहीं समझती कि इस प्रश्न में पड़ने से कोई लाभ होगा। हम जिस विदेश नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह उस नीति का अंग है जिसका राष्ट्र ने पिछले वर्ष अनुसरण किया है । राष्ट्र ने भारत सरकार की नीति का पूरा समर्थन किया है।

श्री समर गुह : यह नीति राष्ट्र के हित में नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक भारत में अनाज लाने का सम्बन्ध है, स्वेज नहर बन्द होने से विलम्ब तथा कठिनाई होगी । परन्तु इससे चावल के सम्भरण पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि इसके परिणाम गम्भीर होंगे। संयुक्त अरब गणराज्य तथा स्पेन से कुछ मात्रा लानी बकाया है । इसमें विलम्ब हो जायेगा, क्योंकि स्पेन के जहाजों को विशेषतया उत्तम आशा अन्तरीप से घूमकर आना पड़ता है। गेहूँ तथा मक्के पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इसराइल की तबाही का उल्लेख किया गया है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम किसी राष्ट्र के विनाश के पक्ष में नहीं हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia Excepting our own nation.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे देश पर हुए आक्रमण के समय संयुक्त अरब गणराज्य के रवैये का उल्लेख किया गया है। चीन के आक्रमण के दौरान संयुक्त अरब गणराज्य की राष्ट्रपति परिषद ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था जिसमें युद्ध विराम का प्रस्ताव किया गया था और चीनी सेना के 4 सितम्बर वाली स्थिति में वापिस जाने की बात कही गई थी। (अन्तर्बाधायें)।

श्री जी० मी० कृपलानी : प्रधान मन्त्री राष्ट्र के दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर रही हैं.....(अन्तर्बाधाय)

अध्यक्ष महोदय : इससे इस गम्भीर मामले पर विचार ठीक प्रकार नहीं हो सकेगा ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The position regarding CIA's part in the elections should be clarified.

Shri M.I.S ndhi (New Delhi): Why the question of CIA is being brought when such an important matter is being discussed here.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसमें भाग लेने वाले सात देशों में हुए समझौते के अनुसार गाजा में तैनात किये गये भारतीय सैनिकों की वापिसी का उत्तर-दायित्व संयुक्त राष्ट्रसंघ पर था । महासचिव के साथ यह तय हुआ था कि वहाँ से हटाये गये सैनिकों को वापिस लाने के लिए एक विमान 8 जून को भेजा जावेगा । भारत अपने सैनिकों को पहले ही वापिस बुलाने के लिए उत्सुक था परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उन्हें विमान द्वारा वापिस बुलाने में सहमत होने में असमर्थता व्यक्त की । मैंने एक बार फिर महासचिव को भेजे गये अपने संदेश में भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से दूर हटाने का अनुरोध किया है, यदि वे भारत में नहीं आ सकते हैं तो उन्हें युद्ध क्षेत्र से यथासम्भव शीघ्र हटाया जा सकता है ।

मुझे आशा हैं कि हम अपना प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा पारित कराने में सफल होंगे । हम किसी भी ऐसे प्रयत्न का समर्थन करेंगे जिससे युद्ध बन्द हो सके और शान्ति स्थापित हो सके ।

सामान्य आय व्ययक 1967–68 सामान्य चर्चा-जारी

GENERAL BUDGET 1967-68 – GENNRAL DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

श्री श्री० ज० डांगे : मैं सरकार से एक बार फिर इस बात का आग्रह करूंगा कि उसे कम से कम चाय, काफी तथा जूतों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिये । पैट्रोल पर उत्पादन शुल्क लगाने का कारण भी समझ में नहीं आता ।

एकाधिकारों पर, विशेषतया उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में; नियंत्रण होना चाहिए और अन्त में एकाधिकार समाप्त कर दिये जाने चाहिये । जब तक मुख्य मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं पर राज्य का नियन्त्रण नहीं होता अथवा राज्य उन्हें अपने हाथ में नहीं ले लेता, तब तक मूल्यों के मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी । उदाहरण के लिए जब तक चीनी पर एकाधिकार समाप्त नहीं होता और सरकार चीनी मिलों को अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक चीनी मिलों में, गन्ने के कृषकों में तथा उपभोक्ताओं में झगड़े बने रहेंगे । मेरा सुझाव है कि कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जावे ।

जिस प्रकार की वस्तुओं का आयात हो रहा है, वह बन्द होना चाहिए । आयात की वस्तुओं के लिए स्थानापन्न वस्तुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए न कि वर्तमान कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात में ढील दी जाये । मुख्य मुख्य वस्तुओं के आयात-निर्यात व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाना चाहिए और व्यापारियों को इस क्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि वे अब भी अधिक बीजक बनाने तथा अन्य कदाचारों में लगे हुए हैं ।

विदेशी पूंजी ने, विशेषतया अमरीकी पूंजी से क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में सभी जानते हैं, होटल उद्योग अथवा अन्य उद्योगों को जो रियायतें दी जा रही हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है ।